



अहिंसा लूपी देवता की आराधना ही हमारे

जीवन को सफलता देने वाला है।

Only worshiping deity of nonviolence

is the key to success in our life.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

# दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 167 ● वर्ष : 12 ● रायपुर, शनिवार 21 दिसम्बर 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

## संक्षिप्त समाचार

आईपीएस जीपी सिंह ने छूटी किया ज्वाइन रायपुर (आरएनएस)। कैरीब गृह मंत्रालय के बाद राज्य के गृह मंत्रालय से दी है। और तरलव है कि, 1994 बैच भाषुपुरे अपराध के आईपीएस युरिजिंडर पाल सिंह को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उनके खिलाफ एकस्टोरेंशन, आय से अधिक संपत्ति और राजद्वारा का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का विवाह राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। इस प्रस्ताव के बाद केंद्र ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी।

**प्रदीप मिश्रा की कथा में अनियत्रित हुई भीड़, कई महिलाएं घोटिए**

मेरठ (आरएनएस)। मेरठ के शताब्दी बाग में चल रही प्रदीप मिश्रा की शिंगमहापुराण के दौरान भीड़ अनियत्रित हो गई। एंट्री गेट पर कई महिलाएं घोट गई हैं। महिलाओं के हड्डी लोटे भी आई हैं। वाराणसी जगत का कथा का आज छाँ और अंतिम दिन है। हर दिन जहां ढेल लाल बद्धालु कथा सुनते पहुंच रहे थे वहां आज श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी लाख पहुंच गई। बाराणसी जगत के व्यवस्था बनाने के काफी दिक्षित आई। नीतर की तरफ पंडाल पूरी तरह फुल हो गया, जबकि बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए थे। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थीं। बाहर जगत श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

## छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रस्त्रकाल के दौरान भाजपा विधायक मोर्तीलाल साहू ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की गायि-



ने कहा कि राशि और ज्यादा दी गई है। पिछली सरकार ने किसानों को छलने का मौत ग्रहण की भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक द्वारा सदन में एजेंट खरीदी की मुदा उत्तरा था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में मुनियोजित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। विना डिपोर्ट के एजेंट सप्लाई की गई, 28 करोड़ की एजेंट खराब हो चुकी है, और भी खराब होने की आशंका है। अॅडिट में पकड़ी गई थी गडबड़ी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साया की गायि-थी, और फिर सदन में हांगामे के बाद कांग्रेस सदस्य बाहर चले गए। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसी बीच किसानों के बारे में बोलने का इनकाल मूँह नहीं रहा। इस आॅडिट में 15 मार्च 2021 तक की गई थी। इस आॅडिट में 193 करोड़ रुपए की खरोड़ी में आपत्ति जताई गई थी। अॅडिट रिपोर्ट में की गई आपत्ति के बावजूद टेंडर निरस्त नहीं किया गया। मोक्षित कारपोरेशन ने अपनी सलाह जारी रखी।

भीतर 11 बच्चों की छात्रावासों में मौत हुई। संडक दुर्घटना, बीमारी, अज्ञात कारणों से मौत हुई। कांग्रेस रूप लेखेश्वर बघेल ने कहा कि, अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। आदिवासी हास्टलों में 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इस पर मंत्री नेता ने कहा कि, यह दीवार के बावजूद किया जाएगा। उसके बाद भाजपा और विष्णुदेव के सांसदों ने कहा कि, यह दीवार के बावजूद किया जाएगा।

## शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नहीं चली संसद, लोकसभा और राज्यसभा अनिवितकाल के लिए स्थगित



मंजूरी दी गई।

राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होने के बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही फिर शुरू होने के बावजूद किया जाएगा। इसके बाद भाजपा और विष्णुदेव कार्यवाही के बावजूद किया जाएगा।

हुई, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम विराज ने लोकसभा को अनिवितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, अंतिम दिन लोकसभा विला ने ने %एक देख एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को परिसर और गेट प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी।

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आये मुंगेली जिले के बच्चे



राजत जर्नरी वर्ष

मंत्रालय महानदी भवन, इंद्रावती भवन और बंजारी मंदिर, सकेल के विद्यार्थियों के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का आयोग जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जारी किया गया।

मंत्रालय का भ्रमण करने के बावजूद भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने

कोच्चुवेली-कोरबा-कोच्चुवेली एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा, यात्रियों को मिलेगी सुगम एवं बेहतर यात्रा सुविधा

रायपुर (विश्व परिवार)। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है इसी क्रम में रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा तैयारी की गई है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 22648 कोच्चुवेली-कोरबा-कोच्चुवेली एक्सप्रेस में 01 जनरल कोच की सुविधा रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 22648 कोच्चुवेली-कोरबा में 19 दिसंबर 2024 से तथा गाड़ी संख्या 22647 कोरबा-कोच्चुवेली एक्सप्रेस में 21 दिसंबर 2024 से उपलब्ध रहेगी।

इस अतिरिक्त जनरल कोच के जुड़ने से इस गाड़ी में 04 जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे ज्यादा लोकों को यात्रा करने की सुविधा भिन्न हो जाएगी। यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा भिन्न हो साथ ही सामान्य कोच में यात्रियों की भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रीगण सुगम एवं आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।

## आम सूचना

में श्रीमती ज्योति शुक्ला निवासी रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन, रायपुर आम जनान को यह सुविधा करती है कि ग्राम कृषीगां (चिक्कली) तसील घर्सीवा, जिला रायपुर (छ.ग.) के ख. नं. - 138 / 1 एवं 139 / 1 कुल रक्कमा - 0.566 हेक्टेर पर मिट्टी उत्थान खदान (गोंद खदान) बनाता - 1000 घन मीटर (इट उत्थान नाप 5,00,000 घन मीटर) प्रति वर्ष के लिये राज सरकार द्वारा आकलन प्रधिकरण, छोटीसागर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1168/एस.इ.आई.ए.छ.ग.। विक्री 181 नाम रायपुर अटल नगर दिनांक 23/10/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरणीय पत्र में दी गई शर्तों के आधारान्वय उक्त सूचना का प्रकाश किया जा रहा है।

श्रीमती ज्योति शुक्ला  
रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन  
रायपुर (छ.ग.)

## कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र. 06, रायपुर (छ.ग.)

### -:: निविदा आमंत्रण सूचना :-

क्रमांक 66/न.पा.नि./जोन क्रमांक - 06 / 2024 - 25

रायपुर दिनांक 19/12/2024

नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्रमांक 06 द्वारा निम्न कार्य देतु निर्धारित SOR (निविदा दिनांक एवं संस्थानित दिनांक) पर लोक कर्म विभाग में पंजीयन ठेकेदारों से निम्नलिखित निम्नांग कार्य देतु ऑनलाइन (Online) निविदा इ-प्रोक्योरमेंट बैब योर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> में आमंत्रित की जाती है।

सिस्टम ठेक्कर कार्य का नाम अनुमानित लालत (रु. लाख में) निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमांक 163196 Rennovation & Repairing work public/ community Toilet under sbm 20.520 13/01/2025

उपरोक्त निम्नांग कार्यों की विस्तृत जानकारी देतु इ-प्रोक्योरमेंट बैब योर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> में एवं कार्यालयीन समय पर नगर पालिक विश्वामपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिक अधिकारी  
नगर पालिक विश्वामपुर  
जिला-सूजपुर (छ.ग.)

निविदा कार्यों की विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा का प्रकार	मद का नाम	अग्रणीत राशि (लाख में)	अपानती राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	एस.ओ.आर.	समय अवधि
1	महामय मंदिर वार्ड क्र. 65 अंतर्गत समाधायिक नवीनी कार्यालयीन के अनुसार निवाका "अ" में निविदा से संर्वीधत आवश्यक दस्तावेज एवं "ब" में निविदा प्रपत्र सील दर्ता दिनांक 02/01/2025 तक निर्धारित राशि सहित आवेदन कार्यालयीन अधिक में जमा किया जा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा देतु आवश्यक दस्तावेज दिनांक 09/01/2025 तक पंजीयन डाक स्प्रिड पोस्ट के माध्यम से सार्व 5.00 बजे तक अधोहस्तानकर्ता के कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रपत्र निविदा देतु अपर्याप्त निविदाकार्यों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समस्त खोली जावेंगी। निविदा	प्रथम	प्रभारी मंदिर निविदा	10.00	7500.00	750.00	FWD Buiding SOR 01.01.2015	05 माह

कार्य के निविदा देतु संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफ्फाक "अ" में  
(1) आयुक नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देते अमानी राशि का एफ.डी.आर (निविदा खोलने तिथि तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति ।  
(2) प्रत्युत दस्तावेजों की संलग्न एवं कार्यों से दो लिफ्फाक पद्धति के अनुसार निवाका के गास।  
(3)पर्स एंजेसी के नाम के वैद्य पंजीयन की प्रति  
(4) बैंक सालेसों की प्रति (5) जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति (6) 3 वर्षों का ITR एवं निविदा तिथि से 3 माह पूर्व का GSTR की प्रति।

लिफ्फाक "ब" में  
(1) निविदा प्रपत्र  
शर्त:- (1) उक्त लिफ्फाक रजिस्टर्ड डाक / स्प्रिड पोस्ट से स्वीकार की जावेंगी। (2) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को प्राप्त की जा सकती है। एवं निविदा जमा करने पर खोलोने के तिथि में अवकाश हो जाने पर आगामी कार्यालयीन दिवस में कार्य संपादित की जावेंगी। (3) डेकेदार / फर्म एवं संस्था के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जी.एस.टी.पी.भाग विभाग से बकाया न होने संबंधी प्राप्ति पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

श्रीमती ज्योति शुक्ला  
रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन  
रायपुर (छ.ग.)

घरों से निकलने वाले सूखा और गीला क्षणों को सफाई मित्र (वाहन) को देवें।

जोन कमिशनर  
जोन क्रमांक - 06  
नगर पालिक निगम, रायपुर

निविदा आमंत्रण सूचना :-

कार्य का निविदा देतु संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफ्फाक "अ" में  
(1) आयुक नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देते अमानी राशि का एफ.डी.आर (निविदा खोलने तिथि तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति ।  
(2) प्रत्युत दस्तावेजों की संलग्न एवं कार्यों से दो लिफ्फाक पद्धति के अनुसार निवाका के गास।  
(3)पर्स एंजेसी के नाम के वैद्य पंजीयन की प्रति  
(4) बैंक सालेसों की प्रति (5) जी.एस.टी.पी.भाग विभाग से बकाया न होने संबंधी प्राप्ति पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

श्रीमती ज्योति शुक्ला  
रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन  
रायपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना :-

कार्य का निविदा देतु संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफ्फाक "ब" में  
(1) आयुक नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देते अमानी राशि का एफ.डी.आर (निविदा खोलने तिथि तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति ।  
(2) प्रत्युत दस्तावेजों की संलग्न एवं कार्यों से दो लिफ्फाक पद्धति के अनुसार निवाका के गास।  
(3)पर्स एंजेसी के नाम के वैद्य पंजीयन की प्रति  
(4) बैंक सालेसों की प्रति (5) जी.एस.टी.पी.भाग विभाग से बकाया न होने संबंधी प्राप्ति पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

श्रीमती ज्योति शुक्ला  
रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन  
रायपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना :-

कार्य का निविदा देतु संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफ्फाक "अ" में  
(1) आयुक नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देते अमानी राशि का एफ.डी.आर (निविदा खोलने तिथि तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति ।  
(2) प्रत्युत दस्तावेजों की संलग्न एवं कार्यों से दो लिफ्फाक पद्धति के अनुसार निवाका के गास।  
(3)पर्स एंजेसी के नाम के वैद्य पंजीयन की प्रति  
(4) बैंक सालेसों की प्रति (5) जी.एस.टी.पी.भाग विभाग से बकाया न होने संबंधी प्राप्ति पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

श्रीमती ज्योति शुक्ला  
रोहिणीपुर कॉलेजी, रुद्र भवन  
रायपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना :-

कार्य का निविदा देतु संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफ्फाक "ब" में  
(1) आयुक नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देते अमानी राशि का एफ.डी.आर (निविदा खोलने तिथि तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति ।  
(2) प्रत्युत दस्तावेजों की संलग्न एवं कार्यों से दो लिफ्फाक पद्धति के अनुसार निवाका के गास।  
(3)पर्स एंजेसी के नाम के वैद्य पंजीयन की प्रति  
(4) बैंक सालेसों की प्रति (5) जी.एस.टी.पी.भाग विभाग से बकाया न होने संबंधी प्राप्ति पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने



# संपादकीय इ

## कानून के आदर की आम हालत की ही एक झलक

साल 2013 में जाकर यूपीए-2 की सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न् रोकने का अधिनियम (संक्षेप में पॉश कानून) बनाया। लेकिन उस पर अमल का हाल क्या है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट के ताजा दिशा-निर्देशों से जाहिर होता है। कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न् रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल पहले जारी किए थे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए, जिन्हें %विशाखा गाइडलाइन्स' के रूप में जाना जाता है। उन दिशा-निर्देशों की भावना के मुताबिक कानून बनाने में 15 साल लग गए। इस बीच कई सरकारें आईं और गईं। 2013 में जाकर यूपीए-2 की सरकार ने यह अधिनियम (संक्षेप में पॉश कानून) बनाया, लेकिन उस पर अमल का हाल क्या है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों से जाहिर होता है। जस्टिस बीबी नागरला और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बैंच ने निर्देश दिया है कि पॉश कानून को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर 2024 तक हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। यह अधिकारी 31 जनवरी 2025 तक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तात्काल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे पॉश अधिनियम की धारा 26 के तहत सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करें और मार्च 2025 तक रिपोर्ट पेश करें। जाहिर है, कानून बनने के 11 साल बाद भी ये सारे कदम नहीं उठाए गए हैं। ताजा निर्देश एक याचिका पर आया, जिसमें गुजारिश की गई है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से पूछे कि क्या सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की समिति का गठन हो गया है। जस्टिस बीबी नागरला की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना है। कोर्ट तीन महीने के भीतर सर्वेक्षण करने और 31 मार्च 2025 तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दे रहा है। पॉश अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि कोई विभाग, मंत्रालय या निजी संगठन अपने यहां जांच समिति का गठन नहीं करता है, तो उस पर 50,000 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मगर ऐसी समितियां आज तक बनी ही नहीं हैं। यह देश में कानून के आदर्शों की आम हालत की ही एक झलक है।

आलेख

## **कोलकाता से राष्ट्रीय गढ़ बंधन का संचालन कैसे**

हरिशंकर व्यास

अगर संसद के शीतकालीन सत्र में पहले तीन हफ्ते की कार्यवाही की रोशनी में विपक्षी राजनीति को देखें तो यह स्वाल उठता है कि अगर राहुल गांधी या मालिकार्जुन खड़गे नेता नहीं होते हैं और ममता बनर्जी को कमान मिलती है तो विपक्षी राजनीति का स्वरूप कैसा होगा ? क्या ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन को एक रखते हुए उसे भाजपा के खिलाफ ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए तैयार कर पाएंगी ? यह बड़ा स्वाल है क्योंकि एक तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ेंगी और वहीं रह कर विपक्षी गठबंधन का संचालन करेंगी । कोलकाता से कैसे राष्ट्रीय गठबंधन का संचालन होगा, यह समझना मुश्किल है । ऐसा लग रहा है कि वे डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की पोजिशनिंग कर रही हैं । वे अपने को राष्ट्रीय नेता और कोलकाता को शक्ति पीठ दिखाना चाहती हैं ताकि बांग्ला मानुष में गर्व की भावना भर सकें और अगला चुनाव जीत सकें । यही राजनीति पिछले साल तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने की था । उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति किया था और अपने को राष्ट्रीय नेता बताना शुरू किया था लेकिन वे चुनाव में पीट गए थे । अब ममता बनर्जी वही राजनीति कर रही है । उनका मकसद किसी तरह से 2026 का विधानसभा चुनाव जीतना है । उनको पता है कि अगला चुनाव बहुत मुश्किल होगा । लगातार 15 साल के राज की एंटी इनकम्वेंसी को किसी बड़े गेमप्लान से ही काउंटर किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक राज्य की पार्टी है । उन्होंने अनेक राज्यों में पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली । इसलिए बाकी

प्रादेशिक पार्टियों के लिए भी उनका नेतृत्व स्वीकार करना मुश्किल होगा। कहने को सभी पार्टियां तैयार हो जाएंगी कि वे विपक्षी गठबंधन की नेता बनें लेकिन वे कोई सामूहिक फैसला सभी पार्टियों से लागू करता पाएंगी इसमें संदेह है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की प्रकृति अकेले चलने की है। वे हमेशा एकला चलो की राजनीति करती हैं और उनकी राजनीति बंगाल केंद्रित होती है। तभी वे चाहे जिस गठबंधन में रहें वहां उनका टकराव चलता रहता है। वे जब कांग्रेस में थीं तो कांग्रेस के सभी नेताओं से उनका झगड़ा चलता था। फिर जब अपनी पार्टी बनाई और भाजपा से तालमेल किया तो भाजपा से उनकी लड़ाई चलती रही और जब कांग्रेस के गठबंधन में आईं तो वहां भी लड़ाई चलती रहीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा को छोड़ कर कांग्रेस से गठबंधन किया और फिर कांग्रेस को छोड़ कर अकेले लड़ीं। अब फिर वे गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं लेकिन उनकी एकला चलो वाली प्रकृति बाधा बनेगी। भारत के अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखें तो किसी प्रादेशिक पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करने की मिसाल नहीं मिलेगी। कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी बनी तो सभी विपक्षी पार्टियों के विलय से बनी थी। हमेशा सबसे बड़ी पार्टी नेतृत्व करती रही है। एनडीए में भी भले टीडीपी या जनता दल यू. के नेता संयोजक होते थे लेकिन नेतृत्व भाजपा के हाथ में ही होता था। संयोजक का पद प्रतीकात्मक होता था। फैसला अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ही करते थे। सरकारों की बात करें तो उस मामले में भी सबसे बड़ी पार्टी के हाथ में सत्ता होने से ही स्थिरता रहती है। चाहे वीपी सिंह की सरकार हो या चंद्रशेखर की या एचडी देवगौड़ा की सरकार हो या आईके गुजराल की हर बार सबसे बड़ी पार्टी के नेता के हाथ में कमान नहीं थी। वाजपेयी की 1998 की सरकार के अपवाद को छोड़ दें तो उसके बाद 1999, 2004 और 2009 में सबसे बड़ी पार्टी ने कमान संभाली और सरकारों ने कार्यकाल पूरा किया। बहरहाल, ममता बनर्जी के समर्थन में यह तरक्कि दिया जा रहा है कि वे भाजपा से लड़ती हैं और सीधी लड़ाई में उसको हरा देती हैं। लेकिन एक प्रदेश में सीधी लड़ाई में भाजपा को हरा देना अगर कोई पैमाना है तो कई नेता दावेदार हो जाएंगे। झारखण्ड में हेमत सोरेन ने भी लगातार दो मुकाबले में भाजपा को हराया है और गठबंधन का भी नेतृत्व किया है। दिल्ली में अरविंद केरीवाल भी लगातार भाजपा को हरा रहे हैं।

ललिता कश्यप

# हालत का हा एक झलक

साल 2013 में जाकर यूपीए-2 की सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने का अधिनियम (संक्षेप में पॉश कानून) बनाया। लेकिन उस पर अमल का हाल क्या है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट के ताजा दिशा-निर्देशों से जाहिर होता है। कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल पहले जारी किए थे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए, जिन्हें %विशाखा गाइडलाइन्स' के रूप में जाना जाता है। उन दिशा-निर्देशों की भावना के मुताबिक कानून बनाने में 15 साल लग गए। इस बीच कई सरकारें आई और गई। 2013 में जाकर यूपीए-2 की सरकार ने यह अधिनियम (संक्षेप में पॉश कानून) बनाया, लेकिन उस पर अमल का हाल क्या है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों से जाहिर होता है। जस्टिस बीवी नागरला और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया है कि पॉश कानून को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर 2024 तक हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। यह अधिकारी 31 जनवरी 2025 तक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे पॉश अधिनियम की धारा 26 के तहत सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करें और मार्च 2025 तक रिपोर्ट पेश करें। जाहिर है, कानून बनने के 11 साल बाद भी ये सारे कदम नहीं उठाए गए हैं। ताजा निर्देश एक याचिका पर आया, जिसमें गुजारिश की गई है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से पूछे कि क्या सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की समिति का गठन हो गया है। जस्टिस बीवी नागरला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना है। कोर्ट तीन महीने के भीतर सर्वेक्षण करने और 31 मार्च 2025 तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दे रहा है। पॉश अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि कोई विभाग, मंत्रालय या निजी संगठन अपने यहां जांच समिति का गठन नहीं करता है, तो उस पर 50,000 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मगर ऐसी समितियां आज तक बनी ही नहीं हैं। यह देश में कानून के आदर की आम हालत की ही एक झलक है।

## आलेख

# कोलकाता से राष्ट्रीय गठबंधन का संचालन कैसे

### हरिशंकर व्यास

अगर संसद के शीतकालीन सत्र में पहले तीन हफ्ते की कार्यवाही की रोशनी में विपक्षी राजनीति को देखें तो यह सबाल उठता है कि अगर राहुल गांधी या मलिकार्जुन खड़े नेता नहीं होते हैं और ममता बनर्जी को कमान मिलती है तो विपक्षी राजनीति का स्वरूप कैसा होगा? क्या ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन को एक रखते हुए उसे भाजपा के खिलाफ ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए तैयार कर पाएंगी? यह बड़ा सबाल है क्योंकि एक तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ेंगी और वहीं रह कर विपक्षी गठबंधन का संचालन करेंगी। कोलकाता से कैसे राष्ट्रीय गठबंधन का संचालन होगा, यह समझना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि वे डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की पोजिशनिंग कर रही हैं। वे अपने को राष्ट्रीय नेता और कोलकाता को शक्ति पीठ दिखाना चाहती हैं ताकि बांग्ला मानुष में गर्व की भावना भर सकें और अगला चुनाव जीत सकें। यही राजनीति पिछले साल तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने की था। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति किया था और अपने को राष्ट्रीय नेता बताना शुरू किया था लेकिन वे चुनाव में पीट गए थे। अब ममता बनर्जी वही राजनीति कर रही है। उनका मकसद किसी तरह से 2026 का विधानसभा चुनाव जीतना है। उनको पता है कि अगला चुनाव बहुत मुश्किल होगा। लगातार 15 साल के राज की एंटी इकमैसी को किसी बड़े गेमप्लान से ही काउंटर किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की तुण्मूल कांग्रेस एक राज्य की पार्टी है। उन्होंने अनेक राज्यों में पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसलिए बाकी प्रादेशिक पार्टियों के लिए भी उनका नेतृत्व स्वीकार करना मुश्किल होगा। कहने को सभी पार्टियां तैयार हो जाएंगी कि वे विपक्षी गठबंधन की नेता बनें लेकिन वे कोई सामूहिक फैसला सभी पार्टियों से लागू करवा पाएंगी इसमें संदेह है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की प्रकृति अकेले चलने की है। वे हमेशा एकला चलोंगी की राजनीति करती हैं और उनकी राजनीति बंगाल केंद्रित होती है। तभी वे चाहे जिस गठबंधन में रहें वहां उनका टकराव चलता रहता है। वे जब कांग्रेस में थीं तो कांग्रेस के सभी नेताओं से उनका झगड़ा चलता था। फिर जब अपनी पार्टी बनाई और भाजपा से तालमेल किया तो भाजपा से उनकी लड़ाई चलती रही और जब कांग्रेस के गठबंधन में आई तो वहां भी लड़ाई चलती रही। उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा को छोड़ कर कांग्रेस से गठबंधन किया और फिर कांग्रेस को छोड़ कर अकेले लड़ीं। अब फिर वे गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं लेकिन उनकी एकला चलोंगी की प्रकृति बाधा बनेगी। भारत के अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखें तो किसी प्रादेशिक पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करने की मिसाल नहीं मिलेगी। कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी बनी तो सभी विपक्षी पार्टियों के विलय से बनी थी। हमेशा सबसे बड़ी पार्टी नेतृत्व करती रही है। एनडीए में भी भले टीटीपी या जनता दल यू के नेता संयोजक होते थे लेकिन नेतृत्व भाजपा के हाथ में ही होता था। संयोजक का पद प्रतीकात्मक होता था। फैसला अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ही करते थे। सरकारों की बात करें तो उस मामले में भी सबसे बड़ी पार्टी के हाथ में सत्ता होने से ही स्थिरता रहती है। चाहे वीपी सिंह की सरकार हो या एचडी देवगौड़ा की सरकार हो या आईके गुजराल की हर बार सबसे बड़ी पार्टी के नेता के हाथ में कमान नहीं थी। बाजपेयी की 1998 की सरकार के अपवाद को छोड़ दें तो उसके बाद 1999, 2004 और 2009 में सबसे बड़ी पार्टी ने कमान संभाली और सरकारों ने कार्यकाल पूरा किया। बहरहाल, ममता बनर्जी के समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है कि वे भाजपा से लड़ती हैं और सीधी लड़ाई में उसको हरा देती हैं। लेकिन एक प्रदेश में सीधी लड़ाई में भाजपा को हरा देना अगर कोई पैमाना है तो कई नेता दावेदार हो जाएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी लगातार दो मुकाबले में भाजपा को हराया है और गठबंधन का भी नेतृत्व किया है। दिल्ली में अरविंद केरीवाल भी लगातार भाजपा को हरा रहे हैं।

गलगल को छोटकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं और हरा धनिया, लहसुन या लहसुन की हरी पीतियां, अदरक, गरम मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पुदीने की खूब सारी चटनी बनाते हैं और गुड़ या चीनी भी डालकर कटे हुए गलगल में अच्छे से मिला लेते हैं त्रूप परिवर्तनशील है। भारत में छह त्रूप पाई जाती हैं- बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमंत और शिशir त्रूप। भारत ही एक ऐसा देश है जहां छह त्रूपों को अनुभव करने का आनंद प्राप्त होता है और यह आनंद केवल उत्तरी भारत में ही प्राप्त हो सकता है। अन्य अधिकतर देशों में केवल चार त्रूप ही पाई जाती हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद त्रूप। यहां हम केवल शरद त्रूप का ही वर्णन करेंगे। भारतीय वैदिक कैलेंडर के अनुसार भारत का नव वर्ष चैत्र मास से मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने इसी समय सृष्टि की रचना की थी। चैत्र मास में बसंत त्रूप आती है और वाकदेवी माता सरस्वती जी ने भी बसंत पंचमी के दिन अपनी वीणा की झंकार से सृष्टि को वाक शक्ति दी थी जिससे प्रत्येक वस्तु को शब्द ध्वनि प्राप्त हुई थी। चैत्र मास के बाद ही अन्य ग्यारह महीने अलग-अलग त्रूपों के संग अठवेलियां करके बीतते हैं। इन्हीं महीनों के अनुसार कौनसी त्रूप किस-किस महीने आती है- 1. बसंत त्रूप- चैत्र से वैशाख महीना। फरवरी से मार्च। 2. ग्रीष्म त्रूप-ज्येष्ठ से आषाढ़। मार्च से जून। 3. वर्षा त्रूप- सावन से भाद्रपद। जुलाई से सितंबर। 4. शरद त्रूप- अश्विन से कार्तिक। अक्टूबर से नवंबर। 5. हेमंत त्रूप- मार्गशीर्ष से पौष। दिसंबर से जनवरी। 6. शिशir त्रूप- माघ से फलमुन। जनवरी से फरवरी। भारत के उत्तरी भाग में अक्टूबर से शरद त्रूप अपना खूब असर दिखाने लगती है। लोग गर्म कपड़े पहनना आरंभ कर देते हैं। परंतु समतल इलाके जैसे पंजाब-हरियाणा में इन्हीं दिनों कम सर्दी होती है और अब अक्टूबर के अंत में धीरे-धीरे बढ़ती है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अधिक रहती है और पर्वत की चोटियों में बर्फगिराने के कारण चलने वाली शीत लहरें समतल क्षेत्र में अपने गुणों का अधिक प्रभाव दिखाती हैं। इसके कारण बहुत से जीव-जंतु सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे- सांप, मेंटक, चीटियां, छिपकलियां, गिलहरियां, खरगोश, जंगली चौह, गोह, किरले, भालू, और भी ठंडे इलाके में रहने

## भारत डोगरा

हर तरफ सम्पत्ता है। जरूरत से भी अधिक सामान है, पर फिर भी आज आदमी दुखी है। उसकी लालसाओं का अंत नहीं। असंतोष और लालच बढ़ रहा है पृथ्वी पर मानव जीवन सर्वप्रथम कब आया, इस पर धार्मिक और वैज्ञानिक लोगों के अलग-अलग मत और विचार हैं, पर उस अदूश्य शक्ति ने पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हर प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जल, वायु, सूर्य, वनस्पति और पृथ्वी के गर्भ में खनिजों के भंडार भर दिए। चौरासी लाख योनियों में मानव ही ऐसा प्राणी है जिसने अपने विवेक के बल पर हर क्षेत्र में अपना विकास किया और निरंतर कर रहा है। वह सर्दी, गर्मी, वर्षा, वर्षे से बचने के लिए गुप्त और धीरे-धीरे बढ़ती है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे अधिक रहती है और पर्वत की चोटियों में बर्फगिराने के कारण चलने वाली शीत लहरें समतल क्षेत्र में अपने गुणों का अधिक प्रभाव दिखाती हैं। इसके कारण बहुत से जीव-जंतु सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे- सांप, मेंटक, चीटियां, छिपकलियां, गिलहरियां, खरगोश, जंगली चौह, गोह, किरले, भालू, और भी ठंडे इलाके में रहने



वाले जीव-जंतु। हेमंत त्रृत्यु यह दिसंबर से जनवरी तक रहती है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। सर्दी से बचने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं। शरीर गर्म कपड़ों से अधिक भरा रहता है। सिर से पांव तक गर्म कपड़ों से लदे रहते हैं। सड़कों पर जगह-जगह पर लोग आग जलाकर ताप रखे होते हैं। घरों में भी लोग हीटर, ब्लोअर तथा गर्म पानी की बोतलों का प्रयोग करते हैं। बर्फीले इलाकों में जहां लंबे समय तक बर्फ रहती है, वहां के लोग सर्दी आने से पहले ही लकड़ी व अनाज का भंडारण कर लेते हैं तथा बकरे के मीट को बड़ी मात्रा में सुखा कर रख लेते हैं। वे एक बड़े कमरे में तंदूर जलाकर तापमान को बढ़ा लेते हैं और तंदूर पर खाना भी बना लेते हैं। यहां के मकान ईंट-सीमेंट के नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे मकान अधिक ठंडे होने के साथ-साथ बर्फ में खराब भी हो जाते हैं। यहां के मकान केवल लकड़ी के बनाए जाते हैं जो बर्फीले मौसम में भी गर्म रहते हैं। यहां के लोग बड़ी मात्रा में भेड़-बकरियां पालते हैं जिससे सर्दी के मौसम में ऊन व मांस प्राप्त किया जा सके। ठंडे इलाकों में खानपान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस मौसम में गर्म तासीर का ही खाना खाया जाता है। तिल, अखरोट और बादाम से तैयार सिड्धु, मांस, मांस से तैयार मो-मो, थुक्पा, जुम्पा। दालों में कुलथ, मोठ तथा अन्य दालें व साग-सब्जियां, सूखे मेवे, मूंगफली। पेय

पदार्थ में नमकीन चाय जिसकी चाय पत्ती एक विशेष प्रकार की होती है। देसी शराब, लुगड़ी इत्यादि समतल इलाकों में भी साग-सब्जियां, कुलथ, मौवा अन्य दालें, कुचालू, घंडियाली, मीट, मछली, चावल मक्की, गेहूँ की रोटी, चाय, कॉफी, शराब, सूखे मेवे मूंगफली, पंजीरी, जिसे कहाँ-कहाँ सुंड भी कहते हैं, न सब खाद्य पदार्थ शरीर को गर्म रखने के लिए खाया जाते हैं। शिशिर ऋतु- यह ऋतु जनवरी से फरवरी महीने में आती है। इसमें भी सर्दी चरम सीमा पर होती है परंतु समतल इलाकों में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण हो जाने के कारण मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आना आरंभ हो जाता है, जिसमें धीरे-धीरे दिन भी बढ़ने लगते हैं और धीरे-धीरे ठिरुतर सर्दी से गुलाबी सर्दी आने लगती है, परंतु पर्वती इलाकों में अभी भी सर्दी चरम सीमा पर होती है। पूर्ण सर्दियों में धूंध और कोहरे की धनी चादर से सूर्य का किरण धरती पर 12.00 से 1.00बजे तक नहीं पहुंच पाती है और दिन छोटे होने के कारण सूर्य जद्दी है अस्त भी हो जाता है, जिसके कारण धरती का तापमान न्यूनतम चला जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य वे उत्तरायण होने से मौसम में बदलाव आने से धूंध और कोहरे का हटना आरंभ हो जाता है और सूर्य की रोशनी सुहावनी लगती है और उष्मित तापमान का आनंद आलगता है। इन ऋतुओं में अधिक सर्दी होने के कारण

अतीत से मिले को युवा पीढ़ी के नसीब से जोड़ें

कार्वता सिसोदेया

# हरिशंकर व्यास

चालास-पचास वर्ष पहल तक मध्यम वयाय पारिवार में दो-चार सूट होते थे। दो जोड़ी जूते घर के लिए और एक जोड़ी जूते आने-जाने के लिए होते थे। गांव में तो परिस्थितियाँ और भी विकर थीं। वहाँ तो लोग साबुन का प्रयोग भी नहीं करते थे। राख या गोमूत्र से कपड़े धोए जाते थे। घर पर फैन-पुराने कपड़ों में टाकियाँ लगाकर पहना जाता था क्योंकि दुकानें बहुत दूर होती थीं। घास की छत और कच्ची मिट्टी की दीवारों के कच्चे मकान होते थे। उस जमाने में आय बहुत कम हुआ करती थी। फिर भी पच्चीस-तीस रुपए मासिक आय वाला व्यक्ति अपने परिवार का सुख सुविधा-पूर्वक निर्वाह करता था। जीवन साधारण और सादगी से भरा होता था। छोटे-छोटे सपने थे। विकास का समय करवट बदलता रहा। धीरे-धीरे विकास की गाड़ी साधारण शहरी जनता से होती हुई गांव तक पहुंच गई। आज संसार की कायाकल्प हो चुकी है। जहाँ किसी समय आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी खरीदना एक सपना होता था। बड़े-बड़े उद्योगपति या टाटा-बिरला जैसे अमीर लोगों के पास ही ये बहूमूल्य वस्तुएं होती थीं। आम आदमी फिर्मों में ही कार, हवाई जहाज आदि देख सकते थे। पर आज गांव के भी हर घर के अंगन में कार, स्कूटर, बाइक खड़े हैं। कल-कारखानों में सामान ढोने को बड़े-बड़े ट्राले-ट्रकों की लाइनें लगी हैं। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गाडियों की बाढ़ से जाम लगा रहता है। संपन्न परिवारों में हर सदस्य के पास अपनी अलग-अलग गाडियाँ होना आम बात हो

कर रहे हैं जिन्हें खनिज कहते हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी सी सूखे से लेकर विशाल जहाज तक खनिजों से ही बनाए जाते हैं। ऊंचे-ऊंचे भवनों, कल-कारखानों, यातायात के साधनों को बनाने में इनका प्रयोग होता है। इनको चलाने के लिए ईंधन भी हमें खनिज से प्राप्त होते हैं। यहां तक कि हमारे भोजन में भी खनिजों का ही अंश है। मशीनरी-औजार, सभी खनिजों से ही बनते हैं। हमारे भोजन, कपड़े, जूते, साबुन, टूथपेस्ट, तेल, बर्तन आदि दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के बनने में खनिजों का प्रयोग किया जाता है। परंतु आज के इस आत्मकेंद्रित और भौतिकतावादी युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के धारों में इतना उलझा है कि ये धारे मकड़ी के जाल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इनसे निकलने का रास्ता और भी जटिल होता जा रहा है। हमने अपने सरल-सहज जीवन को अपनी महत्वाकांक्षाओं की भयंकर राहों से लालच के भयंकर वनों में कुछ इस तरह से भटका दिया है कि खोज, क्रोध, असहनशीलता, हिंसात्मक प्रकृति जैसे कांटे तन को लहूलुहान कर रहे हैं। आज उसे जितना अधिक ऐश्वर्याराम के साधन मिल रहे हैं, उतने ही असंतुष्ट से विचलित मन से अपनी कामनाओं की नौका पर सवार होकर वह सागर में किनारा ढूँढ रहा है, पर कामनाओं के बोझ से लड़खड़ाती नौका को मृगतृष्णा की तरह किनारा नहीं मिल रहा। हर तरफ वस्तुओं का बाजार और कल-कारखानों की भरमार लालच के साथ बढ़ती जा रही है।

# कनाडा में सिख समुदाय आतंकियों के दबाव से त्रस्त

भारत डोगरा

थीं तो कांग्रेस के सभी नेताओं से उनका झगड़ा चलता था। फिर जब अपनी पार्टी बनाई और भाजपा से तालमेल किया तो भाजपा से उनकी लड़ाई चलती रही और जब कांग्रेस के गठबंधन में आई तो वहाँ भी लड़ाई चलती रहीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा को छोड़ कर कांग्रेस से गठबंधन किया और फिर कांग्रेस को छोड़ कर अकेले लड़ीं। अब फिर वे गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं लेकिन उनकी एकला चलो वाली प्रकृति बाधा बनेगी। भारत के अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखें तो किसी प्रादेशिक पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करने की मिसाल नहीं मिलेगी। कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी बनी तो सभी विपक्षी पार्टियों के विलय से बनी थी। हमेशा सबसे बड़ी पार्टी नेतृत्व करती रही है। एनडीए में भी भले टीटीपी या जनता दल यू के नेता संयोजक होते थे लेकिन नेतृत्व भाजपा के हाथ में ही होता था। संयोजक का पद प्रतीकात्मक होता था। फैसला अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ही करते थे। सरकारों की बात करें तो उस मामले में भी सबसे बड़ी पार्टी के हाथ में सत्ता होने से ही स्थिरता रहती है। चाहे वीपी सिंह की सरकार हो या चंद्रशेखर की या एचडी देवगौड़ा की सरकार हो या आईके गुजराल की हर बार सबसे बड़ी पार्टी के नेता के हाथ में कमान नहीं थी। वाजपेयी की 1998 की सरकार के अपवाद को छोड़ दें तो उसके बाद 1999, 2004 और 2009 में सबसे बड़ी पार्टी ने कमान संभाली और सरकारों ने कार्यकाल पूरा किया। बहरहाल, ममता बनर्जी के समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है कि वे भाजपा से लड़ती हैं और सीधी लड़ाई में उसको हरा देती हैं। लेकिन एक प्रदेश में सीधी लड़ाई में भाजपा को हरा देना अगर कोई पैमाना है तो कई नेता दावेदार हो जाएंगे। झारखण्ड में हेमंत सोरेन ने भी लगातार दो मुकाबले में भाजपा को हराया है और गठबंधन का भी नेतृत्व किया है। दिल्ली में अरविंद केरीवाल भी लगातार भाजपा को हरा रहे हैं।

आवाज आने से पूछताछ की जरूरत और बढ़ गई थी पर इन गुस्चरोंने ने ऐसा कुछ नहीं किया और आगे कोई कार्रवाई ही नहीं की। अब जब अन्य तथ्य सामने आ चुके हैं तो स्पष्ट है, जैसा कि जांच रिपोर्ट में भी कहा गया है, कि यह सुनसान इलाके में बम टेस्ट करने का प्रयास था क्योंकि दो वायुयानोंमें बम रखने की तैयारियां उस समय पूरे जोरों पर थीं। यदि समय पर इन खालिस्तानियों से भली-भांति पूछताछ कर ली जाती तो घड़यंत्र को उसी समय रोक पाने की संभावना थी। एक अन्य बड़ा मुद्दा है कि गुपचर एजेंसी सीएसआईएस ने पहले टेंपो पर खालिस्तानी घड़यंत्रकारियों की बहुत सी बातचीत रिकार्ड भी की थी और फिर इसमें पहले कि इस रिकार्डिंग का समुचित विश्लेषण हो पाता, इनको नष्ट कर दिया गया। जांच रिपोर्ट ने इस बारे में इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जैसिफसन की टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया है, जिन्होंने इसे ऐसी लापरवाही बताया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिर, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इस पर चर्चा हुई तो सीएसआईएस का यह पक्ष सामने आया कि उसके एक एजेंट ने खालिस्तानी घड़यंत्रकारियों में घुसपैठ कर ली थी, हालांकि कनिष्ठ हादसे से तीन दिन पहले उसे अलग कर लिया गया। सीएसआईएस का पक्ष, जो प्रकाशित है।



रिपोर्ट में बताया गया है (जसा बाबासा की एक रिपोर्ट में भी छापा) कि उसने अपने इस एंजेंट के बचाव के लिए टेप नष्ट किए। पर ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजेंट के पास जो जानकारी थी, उसका भरपूर उपयोग किया जाता तो इतना समय जरूर मिलता कि घड़यांत्र का पता लगा कर उसे नाकाम कर दिया जाता। पर ऐसा नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो जानकारी सीएसआईएस के पास होती थी वह कनाडियन पुलिस (आरसीएमपी) के साथ ठीक से शेयर नहीं की जाती थी। कनाडा के उच्च स्तर के कुछ सुरक्षा अधिकारियों ने इस बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करनी आरंभ की कि कनाडा में बहुत से आतंकी संगठनों ने डेरा जमा लिया है। सीएसआईएस के पूर्व अध्यक्ष वार्ड एलकाक न अपना उच्चस्तरीय जानकारी के आधार पर सीनेट की एक विशेष समिति को बताया कि अमेरिका को छोड़ दें तो किसी भी अन्य देश की अपेक्षा कनाडा में अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि उनका संस्थान सीएसआईएस की आतंक-विरोधी शाखा ऐसे 50 आतंकवादी संगठनों और इनसे जुड़े 350 व्यक्तियों की जांच कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ये विभिन्न आतंकवादी संगठन आतंकवादी कार्रवाइयों में सहायता देते हैं, आतंकवाद के लिए धन एकत्र करते हैं, प्रोपेंडा और असत्य (डिसइंफ्रामेशन) फैलाने के लिए विभिन्न समुदायों का दोहन-शोषण करते हैं, अप्रवासियों को डराते-धमकाते हैं, आर्टिकियों के लिए कनाडा में सुरक्षित शरण स्थलों की हमला से भी जुड़ा रहा हा। रिपोर्ट न स्पष्ट कहा है कि कई महत्वपूर्ण संदर्भ में कनाडा की सरकार आतंकवाद के नियंत्रण के लिए असरदार कदम उठाने में असमर्थ रही है। रिपोर्ट ने बताया है कि खतरनाक आतंकी संगठनों पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकी और यहां तक कि ऐसे कुछ संगठन परोपकारी कार्य का आवरण लगा कर अपना प्रसार करते हैं, उस पर भी काफी समय तक रोक नहीं लग सकी। उनके विरुद्ध असरदार कार्रवाई करने के बहुत कम उदाहरण कनाडा में देखे गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक दल और नेता भी अपने संकीर्ण स्वार्थी हितों के लिए ऐसी ढील देने की नीति अपनाते हैं। सीएसआईएस की रणनीतिक योजना के पूर्व मुख्य अधिकारी डेविड हैरिस से जब पूछा गया।

व्यवस्था करते हैं, आतंकियों की अमेरिका तक आने-जाने की व्यवस्था करते हैं, और अप्रवासियों की तस्करी करते हैं। यह बयान कनाडा के फेसर इंस्टीट्यूट की अध्ययन रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसका शीषक है %कनाडा'ज इनएडिक्ट रिस्पॉन्स टू टेररिज्म'। रिपोर्ट के लेखक हैं मार्टिन कोलाकोट। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के अतिरिक्त अनेक अन्य तरह के आतंकवादी संगठन भी कनाडा में सक्रिय हैं, और इनका संबंध अनेक अन्य चर्चित आतंकवादी हमलों से भी जुड़ा रहा है। रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कई महत्वपूर्ण संदर्भों में कनाडा की सरकार आतंकवाद के नियंत्रण के लिए असरदार कदम उठाने में असमर्थ रही है। रिपोर्ट ने बताया है कि खतरनाक आतंकी संगठनों पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकी और यहां तक कि ऐसे कुछ संगठन परोपकारी कार्य का आवरण लगा कर अपना प्रसार करते हैं, उस पर भी काफी समय तक रोक नहीं लग सकी। उनके विरुद्ध असरदार कार्रवाई करने के बहुत कम उदाहरण कनाडा में देखे गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक दल और नेता भी अपने संकीर्ण स्वार्थी हितों के लिए ऐसी ढील देने की नीति अपनाते हैं। सीएसआईएस की रणनीतिक योजना के पूर्व मुख्य अधिकारी डेविड हैरिस से जब पृष्ठा गया।







